सिविल विविध

एस. एस. संधावालिया और एस. सी. मित्तल से पहले जे.जे.

साधु राम और एक अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि, उत्तरदाता।

1973 की सिविल रिट संख्या 2842।

3 फरवरी, 1976।

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961 का XXV) (हरियाणा में यथा संशोधित) - धारा 19, 23 और 26 - पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963 - नियम 23 और परिशिष्ट 'सी' (जैसा कि मई, 1973 में था) - सहकारी समिति के उप-नियम जो केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करते हैं - चाहे परिशिष्ट 'सी' का उल्लंघन करें - ऐसे उप-नियमों के अनुसार आयोजित चुनाव - चाहे अवैध हो।

पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज रूल्स 1963 के नियम 23 के तहत तैयार परिशिष्ट 'सी' के नियम 1 (ए) और (जी) में दी गई 'उम्मीदवार' और 'मतदाता' की दो परिभाषाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक उम्मीदवार नहीं हो सकता जब तक कि वह मतदाता होने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला मतदाता न हो। दो शर्तें निर्धारित की गई हैं, अर्थात्, वह या तो एक समिति का शेयरधारक होना चाहिए या एक सदस्य सहकारी समिति का अधिकृत प्रतिनिधि होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इन दो योग्यताओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों में से किसी का भी इरादा है और कानून द्वारा मतदान के अधिकार के साथ निहित किया गया है। सांविधिक प्रावधानों में केवल प्रतिनिधियों के मीडिया के माध्यम से चुनाव के स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि एक सदस्य के पास अपना वोट नहीं होगा और वह केवल अप्रत्यक्ष तरीके से इसका उपयोग करेगा। परिभाषाएं सिद्धांत रूप में नहीं हैं, केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव, या जिसे चुनाव का एक कड़ाई से अप्रत्यक्ष तरीका कहा जा सकता है। परिशिष्ट सी के भाग II, जिसमें समितियों के चुनावों के लिए बहुत विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं, में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो केवल प्रतिनिधियों द्वारा मतदान का कोई संदर्भ देता हो। वास्तव में परिशिष्ट 'सी' के भाग II में नियम 19 आवश्यक निहितार्थ द्वारा मतदाताओं द्वारा वोटों का सीधा प्रयोग दर्शाता है। इसलिए, कानून प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव की मंजूरी नहीं देता है और इस तरह के चुनाव के लिए प्रावधान करने वाली सहकारी समिति के उप-नियम परिशिष्ट 'सी' के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तथापि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी सोसायटी के उपनियम उन सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन या उनके विपरीत नहीं चल सकते हैं जिनके अंतर्गत उन्हें विधिवत पंजीकृत किया गया है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के बीच संघर्ष के मामले में, उप-नियमों को मूल प्रावधानों के लिए रास्ता देना चाहिए। नतीजतन, अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रावधान करने वाले सोसाइटी के उप-नियम जो परिशिष्ट 'सी' के विपरीत हैं, उन्हें कोई वैधता नहीं माना जाना चाहिए और ऐसे उप-नियमों के अनुसार आयोजित कोई भी चुनाव अमान्य है।

(पैरा 7, 8, 9 और 10)

माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा द्वारा 18 सितंबर, 1974 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए खंडपीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति एससी मित्तल की खंडपीठ ने अंततः 3 फरवरी, 1976 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि आप विनम्रतापूर्वक एक उचित रिट / आदेश या निर्देश जारी करें: –

(a) प्रतिवादी संख्या 4 के आदेशों को रद्द करना जिसके द्वारा उन्होंने 16 सितंबर, 1973 को जोन नंबर 5, 6, 7 से इंद्री गन्ना उत्पादक सहकारी समिति का चुनाव तय किया है और प्रतिवादी नंबर 5 (रिटर्निंग ऑफिसर) के 26 मई, 1973 के आदेश को रद्द करना है,

जिसके द्वारा उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 से 10 को जोन नंबर 1 से 4 तक निदेशक घोषित किया है। पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज रूल्स, 1963 के नियम 23 को अवैध, मनमाना, अधिकार क्षेत्र से परे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए यह निर्धारित करने वाली सोसायटी को पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज रूल्स, 1963 के नियम 23 के दायरे से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(b) याचिकाकर्ताओं को आकस्मिक लागत/लागत प्रदान करना।

इसके अलावा प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी संख्या 7 से 10 को इंद्री गन्ना उत्पादक सहकारी समिति की प्रबंध समिति के रूप में काम करने से रोका जाए और 5 सितंबर, 1973 को होने वाले 11 से 16 तक के प्रतिवादियों में से जोन नंबर 5 6 7 से निदेशकों के चुनाव पर वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने तक रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील जीएस संधू ने पैरवी की।

सी बी कौशिक, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए।

भागीरथ दास, वकील, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के लिए।

निर्णय

एस. एस. संधावालिया, न्यायशीश

(1) क्या इंद्री गन्ना उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के उप-नियम 15 में यह प्रावधान किया गया है कि उक्त सोसाइटी के सदस्य अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग करेंगे और उनका अपना कोई वोट नहीं होगा, पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963 के नियम 23 के तहत बनाए गए परिशिष्ट 'सी' का उल्लंघन है, यह प्राथमिक और वास्तव में एकमात्र प्रश्न है जो संदर्भ पर हमारे समक्ष इस रिट याचिका में निर्धारण की मांग करता है।

(2) चूंकि हमारे सामने पेश किया गया एकमात्र कानूनी मुद्दा ऊपर उल्लिखित है, इसलिए यह उससे संबंधित तथ्यों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त है। दो याचिकाकर्ता इंद्री गन्ना उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्य हैं, (इसके बाद सोसाइटी कहा जाता है) जो पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत विधिवत पंजीकृत निकाय है। गन्ना आयुक्त, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 4) ने 31 मई, 1973 को जोनल आधार पर सोसायटी की प्रबंध समिति के चुनाव को निर्धारित किया और सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों (प्रतिवादी संख्या 5) को इसके लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। चुनाव कार्यक्रम में यह प्रावधान था कि नामांकन पत्र 23 मई, 1973 को दाखिल किए जाने थे; जिनकी जांच अगले दिन की जानी थी; नामांकन वापस लेने और चुनाव चिन्ह ों के आवंटन की तारीख 2 मई, 1973 तय की गई थी। इस तारीख को, रिटर्निंग अधिकारी ने उत्तरदाताओं संख्या 7 से 10 को जोन नंबर 1 से 4 तक सोसाइटी की प्रबंध समिति के लिए निर्विरोध चुने जाने के रूप में घोषित किया। तथापि, 30 मई, 1973 को अनुलग्नक क के तहत गन्ना आयुक्त, हरियाणा ने अगले दिन होने वाले चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इस स्थगन के कारणों या वैधता पर ध्यान देना अनावश्यक है और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि जोन Nos_ 5 से 7 तक के व्यक्तियों का चुनाव अंततः 16 सितंबर, 1973 के लिए तय किया गया था।

(3) याचिकाकर्ता के मामले का मूल यह है कि उपरोक्त चुनावों को सोसाइटी के उप-नियमों (विशेष रूप से उप-नियम 15) के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से लड़ा जाना आवश्यक था, जो पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963 के नियम 23 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के तहत बनाए गए परिशिष्ट 'सी' का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते थे। यह दावा किया गया है कि वैधता के लिए इस तरह के चुनाव परिशिष्ट 'सी' के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह बताया गया है कि यद्यपि राज्य में सभी सहकारी उपभोक्ता भंडारों के चुनाव पहले प्रतिनिधियों के माध्यम से आयोजित किए जाते थे, लेकिन परिशिष्ट 'सी' के लागू होने और लागू होने के बाद ये चुनाव अब परिशिष्ट 'सी' के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अन्य सभी समितियों की तरह आयोजित किए जा रहे हैं। नतीजतन, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान सहित सभी गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव नियम 23 और परिशिष्ट 'सी' के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि उक्त प्रावधान के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार और

उसमें मतदान करने का अधिकार सीधे समाज के प्रत्येक सदस्य में निहित है, न कि उन मतदाताओं के प्रतिनिधियों की एजेंसी के माध्यम से। इसलिए, यह आरोप लगाया जाता है कि उप-नियमों में इस आशय का कोई भी प्रावधान निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ नहीं टिक सकता है और इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से उक्त उप-नियमों के अनुसार आयोजित सभी चुनाव अमान्य हैं। यह प्रार्थना की जाती है कि सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों के रूप में प्रतिवादी संख्या 7 से 10 के चुनावों को रद्द कर दिया जाए क्योंकि यह प्रतिनिधियों के माध्यम से आयोजित किया गया था और इसके अलावा प्रतिवादी नंबर 4 के आदेश 16 सितंबर को जोन नंबर 5 से 7 तक समान तरीके से चुनाव तय करने के लिए थे। 1973 को रद्द किया जाए।

(4) रिटर्न आधिकारिक प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से दाखिल किया गया है। इसके संगत पैराग्राफ में यह दावा किया गया है कि सोसायटी की प्रबंध समिति का चुनाव उत्तर देने वाले प्रतिवादियों के निर्देशन में होना है। किसी भी तरह से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। विवरणी के पैरा 13(ख) में यह कहा गया है कि सोसायटी एक केन्द्रीय सोसायटी है और इसकी प्रबंध समिति के चुनाव नियम 23 के अंतर्गत बनाए गए परिशिष्ट ग के पैरा द्वितीय के उपबंधों के अनुसार किए जाने हैं। तथापि, यह दोहराया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर चुनाव कराया जाना चाहिए। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि सोसायटी के उपनियमों में स्वयं प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंध समिति के चुनाव का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों को कानूनी और वैध होने के लिए दोहराया जाता है और यह प्रतिवादी का मामला है कि नियमों के तहत परिशिष्ट 'सी' के प्रवर्तन के आधार पर ये निरर्थक या अवैध नहीं हो गए हैं।

(5) अनिवार्य रूप से, पहले अधिनियम की धारा 19 का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जो वोट का प्रयोग करने के तरीके के बारे में कार्डिनल नियम निर्धारित करता है। पंजाब और हरियाणा राज्यों के गठन के बाद अधिनियम में भौतिक परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान मामला हरियाणा राज्य से संबंधित है, इसलिए यह प्रासंगिक प्रावधान का पालन करने के लिए पर्याप्त है जैसा कि यह अब है: -

“19. सहकारी समिति का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने मत का प्रयोग करेगा और किसी भी सदस्य को प्रॉक्सी द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते कि -

(a) एक सहकारी समिति जो किसी अन्य सहकारी समिति की सदस्य है, नियमों के अधीन रहते हुए, अपने सदस्यों में से एक को दूसरी सोसाइटी के मामलों में अपनी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकती है;

(b) धारा 15 के खंड (1) के तहत सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए अधिकृत व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघों का एक वर्ग या वर्ग, नियमों के अधीन रहते हुए, सोसाइटी के मामलों में अपनी ओर से मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों में से एक को नियुक्त कर सकता है।

कानूनी इतिहास के मामले के रूप में, हालांकि, यह देखा जा सकता है कि मूल रूप से धारा 19 में दो उप-धाराएं थीं और 1971 के हरियाणा अधिनियम संख्या 13 में संशोधन करके उप-धारा (2) को हटा दिया गया था और ऊपर दिए गए परंतुक को क़ानून में जोड़ा गया था। उपरोक्त धारा 19 की सरल भाषा का अर्थ यह है कि यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से मतदान का उपयोग करने का प्रावधान करता है। हालांकि, इस नियम के दो अपवाद अब परंतुक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसके खंड (क) में स्पष्ट रूप से किसी विधिक व्यक्ति (अर्थात् एक सहकारी समिति जो किसी अन्य सहकारी समिति की सदस्य है) द्वारा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान करने के तरीके का प्रावधान है। इसी प्रकार, खंड (ख) में यह उपबंध है कि जहां कोई वर्ग या व्यक्तियों का वर्ग या व्यक्तियों का समूह या संघ किसी सहकारी समिति का सदस्य बन गया है, वे अपने प्रतिनिधियों में से किसी एक को सोसायटी के मामलों में अपनी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 19 में ही सीधे तौर पर प्रावधान है कि वास्तविक व्यक्ति जो सहकारी समिति के सदस्य हैं, केवल चुनाव के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने वोटों का प्रयोग कर सकते हैं।

(6) इसलिए, हम यह निर्धारित करने के लिए अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की ओर रुख कर सकते हैं कि क्या केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से मतदान उनके द्वारा अधिकृत या पवित्र है और आगे क्या वे सहकारी समिति के सदस्य में निहित व्यक्तिगत रूप से मतदान के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान है कि सहकारी समिति की समिति के सदस्यों का निर्वाचन विहित रीति से किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचित नहीं होगा जब तक कि वह समिति का शेयरधारक न हो। चुनाव कराने के तरीके को विस्तार से निर्धारित करने के उद्देश्य से सांविधिक नियम बनाए गए हैं। इस संदर्भ में प्राथमिक नियम निम्नलिखित प्रभाव के लिए नियम 23 है:: —

"समिति का चुनाव: सहकारी समिति की समिति के सदस्यों का चुनाव परिशिष्ट 'सी' में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

यह हमारे सामने पार्टियों का आम मामला है कि लागू किए गए चुनाव की वैधता को कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए क्योंकि यह 26 मई, 1973 को मौजूद था, जब प्रतिवादी संख्या 7 से 10 को निर्वाचित घोषित किया गया था। इसलिए, परिशिष्ट ग की ओर मुड़ते हुए, जैसा कि यह उस समय हरियाणा राज्य में था, भौतिक उपबंध इसके भाग-I में हैं जिसमें इस परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं और समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता निर्धारित करने वाले दो बुनियादी नियम शामिल हैं। विशेष संदर्भ यहां 'उम्मीदवार' और 'मतदाता' शब्दों के लिए दी गई परिभाषा के योग्य है, जिन्हें संदर्भ की सुविधा के लिए विस्तार से उद्धृत किया गया है: –

> "1(a) 'उम्मीदवार का अर्थ है एक मतदाता, जो अपना नामांकन दाखिल करता है (चुनाव की तलाश करने के लिए कागजात; और
>
> (छ) 'मतदाता' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो शेयरधारक है या किसी सदस्य सहकारी समिति का अधिकृत प्रतिनिधि है, जो चुनाव में भाग लेने के लिए विधिवत योग्य है।

(7) उपरोक्त दो परिभाषाओं को एक साथ पढ़ना (जैसा कि वे आवश्यक रूप से हैं) यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति तब तक उम्मीदवार नहीं हो सकता जब तक कि वह मतदाता न हो। मतदाता होने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, दो शर्तें निर्धारित की जाती हैं, अर्थात्, वह या तो एक समिति का शेयरधारक होना चाहिए या एक सदस्य सहकारी समिति का अधिकृत प्रतिनिधि होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इन दो योग्यताओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों में से किसी का भी इरादा है और कानून द्वारा मतदान के अधिकार के साथ निहित किया गया है। सांविधिक प्रावधानों में केवल प्रतिनिधियों के मीडिया के माध्यम से चुनाव के स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि एक सदस्य के पास अपना वोट नहीं होगा और वह केवल अप्रत्यक्ष तरीके से इसका उपयोग करेगा। इसलिए, मुख्य रूप से इस मुद्दे का मूल यह है कि क्या केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से एक अप्रत्यक्ष चुनाव वैध है या क्या कानून के लिए शेयरधारकों द्वारा वोट के प्रत्यक्ष प्रयोग की आवश्यकता है जो वास्तविक व्यक्ति हैं या सदस्य सहकारी समिति के मामले में उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से। हमें डर है कि भौतिक समय पर जो परिभाषाएं खड़ी थीं, वे केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव के सिद्धांत में शामिल नहीं थीं या जिसे चुनाव का एक पूरी तरह से अप्रत्यक्ष तरीका कहा जा सकता है।

(8) उपर्युक्त दृष्टिकोण तब और मजबूत हो जाता है जब परिशिष्ट ग के भाग-II का उल्लेख किया जाता है जिसमें शीर्ष केन्द्रीय सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंकों की समितियों के चुनावों के लिए बहुत विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं। यहां तक कि प्रतिवादियों का यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि परिशिष्ट 'सी' के भाग II के उपर्युक्त प्रावधान वर्तमान चुनावों पर लागू होते हैं। तैंतीस विस्तृत नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केवल प्रतिनिधियों द्वारा मतदान का कोई संदर्भ देता हो। वास्तव में परिशिष्ट 'सी' के भाग II में नियम 19 आवश्यक निहितार्थ द्वारा मतदाताओं द्वारा वोटों का सीधा प्रयोग दर्शाता है।

(9) हरियाणा राज्य द्वारा परिशिष्ट 'ग' के भाग 1 में किए गए बाद के संशोधन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पहले के प्रावधानों में प्रतिनिधियों के मीडिया के माध्यम से चुनाव की आवश्यकता नहीं थी। 31 अक्टूबर, 1974 को पंजाब सहकारी समिति (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 1974 को प्रख्यापित किया गया था। इन प्रावधानों ने मतदाता की परिभाषा में संशोधन किया जैसा कि वह पहले था और निर्देश दिया कि इसके लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

" (g) 'मतदाता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है, जो या तो एक शेयरधारक है या किसी सदस्य सहकारी समिति का अधिकृत प्रतिनिधि है; चुनाव में भाग लेने के लिए विधिवत योग्य है और इसमें शामिल हैं, अधिनियम की धारा 23 के परंतुक के अनुसार निर्वाचित या चयनित सहकारी समिति का प्रतिनिधि।

पूर्वोक्त परिवर्तन वास्तव में महत्वपूर्ण है और नया प्रावधान, स्पष्ट रूप से मतदाताओं की परिभाषा के भीतर लाया गया है, जो अधिनियम की धारा 23 के परंतुक के अनुसार निर्वाचित या चयनित सहकारी समिति का प्रतिनिधि है। तथापि, जिस प्रासंगिक अवधि (मई, 1973 में) के संबंध में हम चिंतित हैं, उसके लिए मतदाता की परिभाषा में कोई संशोधन नहीं किया गया था और इसके दायरे में प्रतिनिधियों की कोई अवधारणा अथवा चुनाव का अप्रत्यक्ष तरीका नहीं था। बाद का संशोधन वास्तव में याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे बढ़े मामले को मजबूत करता है। यदि मूल परिभाषा का उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव की परिकल्पना करना था और इसके भीतर प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव की परिकल्पना की गई थी, तो स्पष्ट रूप से परिभाषा में संशोधन करने और प्रतिनिधियों के मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से इसके भीतर एक चुनाव शामिल करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। बाद के संशोधन को केवल अधिशेष या निरर्थक नहीं माना जा सकता है। इसका सीधा सा इरादा मतदाता की परिभाषा के भीतर लाने का था, जो पहले इसमें शामिल नहीं था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि 26 मई, 1973 को, जब प्रतिवादी संख्या 7 से 10 को

निर्वाचित घोषित किया गया था, कानून ने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव को मंजूरी नहीं दी थी। इस प्रकार इस माध्यम से उनका चुनाव जारी नहीं रह सकता है।

(10) यह सच है कि सोसायटी के उपनियमों में गांव में सोसायटी के सदस्यों में से प्रत्येक 15 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए एक अप्रत्यक्ष मोड की परिकल्पना और प्रावधान किया गया था। तथापि, यह भी समान रूप से सुविचारित है कि किसी सोसायटी के उपनियम उन सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन या उनके विपरीत नहीं चल सकते जिनके अंतर्गत उन्हें विधिवत पंजीकृत किया गया है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के बीच संघर्ष के मामले में, उप-नियमों को मूल प्रावधानों के लिए रास्ता देना चाहिए। नतीजतन, सोसाइटी का उप-नियम 15, जो प्रासंगिक समय में परिशिष्ट 'सी' (जो चुनाव के तरीके को निर्धारित करता था) के प्रावधानों के साथ प्रत्यक्ष और स्पष्ट विरोधाभास में था, को कोई वैधता नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए उप-नियमों के अनुसार आयोजित कोई भी चुनाव, जो उस समय मौजूद वैधानिक प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी था, को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(11) इस निर्णय से अलग होने से पहले, मैं विद्वान संदर्भ ति न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का संदर्भ देना आवश्यक समझता हूं। पंडित जे द्वारा तय किए गए फैसले की सत्यता के बारे में संदेह इस [1]आधार पर डाला गया था कि शायद अधिनियम की धारा 23 के परंतुक के सही प्रभाव को उनके सामने पर्याप्त रूप से प्रचारित नहीं किया गया था। हमने हरियाणा में यथा संशोधित अधिनियम की धारा 23 के उपबंधों की बारीकी से जांच की है और इसे संदर्भ की सुविधा के लिए विस्तार से निर्धारित किया जा सकता है:-

“23 (1) सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकारी सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा:

परन्तु जहाँ सहकारी समिति के उपनियमों में ऐसे उपनियमों के अनुसार निर्वाचित या चयनित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर छोटे निकाय के गठन का प्रावधान है, वहाँ छोटा निकाय सामान्य निकाय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएँ या जो सोसायटी के उपनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएँ।

हमारे विचार से उपर्युक्त परंतुक किसी भी तरह से भौतिक समय पर सोसायटी की प्रबंध समिति के चुनाव आयोजित करने के तरीके से संबंधित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। इस धारा को समग्र रूप से देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह पहले प्राथमिक सिद्धांत निर्धारित करता है कि सहकारी समिति में अंतिम अधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित है। इसके लिए एक शर्त इस शर्त के साथ संलग्न की गई है कि एक छोटा निकाय सामान्य निकाय में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इस प्रकार निर्दिष्ट हैं और इसके उप-नियमों में प्रदान की गई हैं। उत्तरदाताओं की ओर से, यह इतना प्रचारित नहीं किया गया था, और परिणामस्वरूप हम यह मानने में असमर्थ हैं कि यह परंतुक किसी भी तरह से प्रबंध समितियों के चुनाव के विस्तृत तरीके को नियंत्रित करेगा, जिसे नियम 23 में विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया है। हुकम सिंह के मामले (सुप्रा) का अनुपात हमें उपरोक्त प्रावधान से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं लगता है और अभी भी इस क्षेत्र को बनाए रखेगा। किसी भी मामले में हमारा विचार है कि जहां तक सोसायटी की प्रबंध समिति के चुनाव की वैधता के वर्तमान मुद्दे का संबंध है, उक्त परंतुक प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित नहीं होता है।

(12 तदनुसार, हम सोसायटी के उस उप-नियम को मानते हैं कि प्रासंगिक समय वैधानिक प्रावधानों के साथ संघर्ष में था और इसलिए कोई वैधता नहीं थी। उक्त उप-कानून और उससे जुड़े लोगों के अनुसार आयोजित प्रतिवादी संख्या 7 से 10 का चुनाव इस प्रकार अवैध था और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। इन शर्तों में रिट याचिका की अनुमति दी जाती है लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एस. सी. मित्तल, जे. मैं सहमत हूं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

[1] सी.डब्ल्यू. 365/66, 20 मई, 1966 को तय किया गया।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी